



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 90]
No. 90]नई दिल्ली, ब्रह्मस्पतिवार, फरवरी 28, 2008/फाल्गुन 9, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 28, 2008/PHALGUNA 9, 1929

कोरपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2008

सा.का.नि. 113(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 637क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) तारीख 26 जुलाई, 2001 में प्रकाशित तत्कालीन विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) में, भारत सरकार की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 555(अ), तारीख 26 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के खण्ड (1) में उप-खण्ड (घ), की मद (1) के प्रथम परन्तुक में सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी और परन्तुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

“सारणी

निषेपों में शुद्ध स्थामित्वाधीन निधि का अनुपात (31-3-2007 के अनुसार)

तारीख, जिस तक कम्पनी द्वारा 1: 20 की विहित अधिकतम सीमा को प्राप्त करना अपेक्षित था

विस्तारित की गई वह तारीख, जिस तक कम्पनी द्वारा निर्धारित 1: 20 की अधिकतम विहित सीमा प्राप्त की जानी है

(क) 1: 20 तक	31-3-2007	31-3-2007
(ख) 1: 20 से अधिक किन्तु 1: 30 तक	31-3-2007	31-3-2009
(ग) 1: 30 से अधिक एवं उससे अधिक	31-3-2007	31-3-2010—इस शर्त के अधीन रहते हुए कि कम्पनी 31-3-2009 तक 1: 30 के अनुपात को प्राप्त करें।

परन्तु यदि ऐसी स्वीकृति या पुनर्विलोकन, विहित अनुपात का उल्लंघन करता है तो उपरोक्त (क) के अधीन आने वाली कम्पनियों को नए निषेपों को स्वीकार नहीं करना चाहिए या न ही विद्यमान निषेपों का पुनर्विलोकन करना चाहिए और (ख) और (ग) के अधीन आने वाली कम्पनियों को उनके द्वारा विहित अनुपात प्राप्त करने तक, नए निषेपों को स्वीकार नहीं करना चाहिए और न ही विद्यमान निषेपों का पुनर्विलोकन करना चाहिए :

परन्तु यह और कि उपरोक्त सारणी में वर्णित तारीख को बढ़ाने के लिए किसी कम्पनी या उनके प्रतिनिधि निकाय से कोई अनुरोध ग्रहण नहीं किया जाएगा और विहित अनुपात का जारी उल्लंघन जारी रहने से शास्त्रिक उपबंध प्रभावी हो जाएंगे जिनमें व्यतिक्रम करने वाली निधि कम्पनियों की अधिसूचना रद्द किया जाना सम्भिलित है।"

[फा. सं. 4/2/2007-सं.एल VI]

वाई. एस. मलिक, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 555 (अ), तारीख 26 जुलाई, 2001 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात्, संख्यांक सा.का.नि. 308(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2002, सा.का.नि. 384(अ), तारीख 29 मई, 2002, सा.का.नि. 408(अ), तारीख 31 मई, 2002, सा.का.नि. 775(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2003 और सा.का.नि. 202(अ), तारीख 31 मार्च, 2006 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2008

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 637 A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Department of Company Affairs) number G.S.R.555(E) dated the 26th July, 2001, published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 26th July, 2001, namely :—

In the said notification, in clause (1), in sub-clause (d), in item (i), in the first proviso, for the Table, the following Table and the provisos shall be substituted, namely :—

"TABLE

Ratio of Net Owned Fund to Deposits (as on 31-3-2007)	Date by which the company was required to achieve the prescribed ceiling of 1 : 20	Extended date by which the company has to achieve the prescribed ceiling of 1 : 20
(a) Up to 1 : 20	31-3-2007	31-3-2007
(b) More than 1 : 20 but up to 1 : 30	31-3-2007	31-3-2009
(c) More than 1 : 30 and above	31-3-2007	31-3-2010—subject to the condition that the company achieves the ratio of 1 : 30 by 31.3.2009

Provided that the companies covered under (a) above should not accept fresh deposits or renew existing deposits if such acceptance or renewal leads to violation of the prescribed ratio and the companies covered under (b) and (c) should not accept fresh deposits or renew existing deposits till they achieve the prescribed ratio :

Provided further that no request for extension of date mentioned in the Table above shall be entertained from any company or their representative body and the continued violation of the prescribed ratio would attract penal provisions including de-notification of the defaulting nidhi companies".

[F. No. 4/2/2007-CL-VI]

Y. S. MALIK, Jt. Secy.

Foot Note :—Principal Notification was published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* Number G.S.R.555(E) dated 26th July, 2001 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 308(E) dated the 4th April, 2002, G.S.R.384(E) dated the 29th May, 2002, G.S.R.408(E), dated the 31st May, 2002, G.S.R. 775(E) dated the 29th September, 2003 and G.S.R.202(E) dated the 31st March, 2006.